



पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब सामरिक गठजोड़ का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

निधि कटियार¹, प्रो० (डॉ०) डी० सी० कटियार²

¹शोधार्थी (रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन), पी०पी०एन० कॉलेज, कानपुर (उ०प्र०)।

¹Corresponding Author Email: katiyar.nidhi99@gmail.com

²विभागाध्यक्ष (रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन), पी०पी०एन० कॉलेज, कानपुर (उ०प्र०)।

Abstract (सारांश)

संप्रति 7 अगस्त को पाकिस्तान- तुर्किये- सऊदी अरब के मध्य हुए रणनीतिक समझौते के परिपेक्ष्य में वर्तमान भू-राजनीति में शक्ति-संतुलन की प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का अध्ययन इस शोध पत्र में शामिल है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था प्रमुख शक्तियों के प्रभाव तक सीमित न रहकर बहुध्रुवीयता, सामरिक साझेदारियों, क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं, पश्चिम-एशिया, दक्षिण-एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने क्षेत्रीय शक्तियों को अपने पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर रक्षा, सुरक्षा, कूटनीति एवं आर्थिक सहयोग के रूप में नए रणनीतिक सहयोग विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब की विदेश नीति, क्षेत्रीय हित एवं सुरक्षा प्राथमिकताएं भिन्न-भिन्न होने के बावजूद रक्षा उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, रणनीतिक संवाद, आतंकवाद-रोधी सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इनके हितों का अभिसरण दिखाई देता है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और रणनीतिक स्थिति, तुर्किये की उभरती रक्षा-तकनीकी एवं सैन्य औद्योगिक क्षमता तथा सऊदी अरब की ऊर्जा, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभाव क्षमता इस सहयोग को एक महत्वपूर्ण सामरिक आधार प्रदान करती है। इस दृष्टि से यह संबंध केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित न रहकर व्यापक क्षेत्र शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

यह शोध पत्र पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के रणनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि, तीनों देशों की विदेश नीतियों में आने वाले बदलाव और शक्ति संतुलन का गहन विश्लेषण करता है। साथ ही यह शोध पत्र इस नए गठजोड़ की तुलना नाटो जैसी संस्थाओं से करता है तथा अमेरिका, चीन, रूस जैसी महाशक्तियों की भूमिका को प्रदर्शित करता है एवं चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न संभावित चुनौतियों का विश्लेषण कर उसका निदान प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य शब्द- पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब सामरिक गठजोड़, राष्ट्रीय सुरक्षा, पश्चिम-एशिया, दक्षिण-एशिया, सुरक्षा सहयोग, भू-राजनीति, शक्ति-संतुलन

भूमिका

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के पश्चात् कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ जहाँ वैश्विक राजनीति में सामूहिक सुरक्षा तथा सैन्य गठबंधन का महत्व तेजी से बढ़ा। युद्ध की विनाशकारी परिस्थितियों के बाद वैश्विक राजनीति में स्थाई शांति तथा सामूहिक सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तथा तमाम सैन्य संधियों का निर्माण किया गया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य बढ़ते संघर्ष के परिणामस्वरूप अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना 1949 में हुई, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था। इसी के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ द्वारा 1955 में वारसा पैक्ट बनाया गया, जिसने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रों को एक सामूहिक सैन्य सुरक्षा ढांचे में संगठित किया। इस प्रकार विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। इसी दौरान साम्यवादी विस्तार को सीमित करने के उद्देश्य से 1954 में सीटो एवं 1955 में बगदाद पैक्ट की स्थापना की गई, बाद में बगदाद पैक्ट के पुनर्गठन से सेंटो अस्तित्व में आया। इन संधियों ने सामूहिक रक्षा, सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणा को बल दिया। अंततः यह संधियाँ प्रभावी एवं स्थाई सैन्य गठबंधन के रूप में सफल न होने के कारण कुछ समयान्तराल बाद अपने-अपने स्वरूप को खोती गईं और अंत में आज नाटो शेष बचा है। इन ऐतिहासिक सुरक्षा व्यवस्थाओं

से स्पष्ट होता है कि साझा हितों के आधार पर विभिन्न देश सामूहिक सुरक्षा तंत्र विकसित करते हैं। इसी व्यापक पृष्ठभूमि के संदर्भ में इस शोध पत्र में पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के मध्य हुई रक्षा संधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके इसके निष्कर्षों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मक्का रक्षा संधि पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब द्वारा 7 अगस्त 2026 को मक्का में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, जो पश्चिम एशिया में विकसित हो रही सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह समझौता सितंबर 2025 के सऊदी अरब-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर आधारित है, जिसमें पहले ही यह निर्धारित किया गया था कि किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों के विरुद्ध हमला माना जाएगा। वहीं तुर्किये के इस समझौते में शामिल होने से यह व्यवस्था सऊदी अरब-पाकिस्तान सुरक्षा संबंध से आगे बढ़कर खाड़ी, दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले अंतर क्षेत्रीय ढाँचे में विस्तृत हो गई है। इस समझौते को रक्षात्मक स्वरूप का बताया गया है तथा इसमें राजनीतिक एवं सैन्य परामर्श, लॉजिस्टिक्स सहयोग, वायु एवं मिसाइल रक्षा तथा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता का प्रावधान है। इस समझौते के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसी एक सदस्य देश के विरुद्ध सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। साथ ही इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया गया है, परन्तु इसका दुरुपयोग ही हुआ क्योंकि समस्त देश में यू०एन०ओ० अपनी सेनाएँ भेज कर सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकती थी इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसका दुरुपयोग कर नाटो और वारसा जैसे गुट खड़े हुए। जिन्होंने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जमकर शस्त्रीकरण करा, जो हमारी सभ्यता के लिए खतरा बना। औपचारिक रूप से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के रूप में जाना जाने वाला यह समझौता तीनों देशों के मध्य सामूहिक सुरक्षा, प्रतिरोध, सैन्य समन्वय एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के मध्य उभरते सामरिक गठजोड़ को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना अनिवार्य है। तीनों देशों के मध्य सामरिक सम्बन्धों की नींव दशकों पुराने द्विपक्षीय सम्बन्धों, राजनीतिक, धार्मिक, रक्षा सहयोग की नींव पर आधारित है। समय-समय पर तीनों देशों के संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन होते रहे हैं, परन्तु इनके मध्य रक्षा और सुरक्षा सहयोग से आपसी संबंधों का प्रमुख आधार बना रहा है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के मध्य ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से धार्मिक सामानता, आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा निर्भरता के त्रिआयामी आधार पर लंबे समय से मौजूद रहे हैं। सऊदी अरब में इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं, जिस कारण वह मुस्लिम विश्व में विशेष धार्मिक एवं राजनीतिक महत्व रखता है तथा स्वयं को इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में देखता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान स्वयं को इस्लामी दुनिया की प्रमुख शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। दोनों देशों के मध्य सैन्य एवं रक्षा सहयोग 1960 के दशक से मजबूत होना प्रारंभ हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के द्वारा सऊदी अरब के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में योगदान दिया गया। शीत युद्ध और 1979 के अफगान संकट के दौरान कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हित एक दूसरे के अनुरूप रहे। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को कूटनीतिक, राजनीतिक, तेल और आर्थिक समर्थन प्राप्त होता रहा है।

पाकिस्तान और तुर्किये के बीच संबंधों की शुरुआत पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद से ही मित्रवत रही है। दोनों देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा संबंधों का समय के साथ विस्तार हुआ। शीत युद्ध के दौरान दोनों देश पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था के निकट रहे तथा बगदाद पैक्ट और सेंटो जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में सहयोगी रहे। 21वीं सदी में रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सुरक्षा तकनीकी, उत्पादन ने दोनों देशों के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया है। साथ ही तुर्किये द्वारा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी दृष्टिकोण को समर्थन दिया गया है, जिस कारण दोनों देशों के मध्य रणनीतिक एवं राजनीतिक निकटता बढ़ी है। साथ ही वर्तमान में भी ऑपरेशन सिंदूर में तुर्किये ने पाकिस्तानी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए सैन्य सहायता उपलब्ध कराई है। वर्तमान में तुर्किये पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, इस प्रकार दोनों देशों के मध्य संबंध ऐतिहासिक राजनीतिक एवं औपचारिक रूप से सकारात्मक रहे हैं।

सऊदी अरब और तुर्किये के मध्य संबंधों की नींव ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय-संतुलन से जुड़ी रही है। दोनों देशों के मध्य लंबे समय से आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध रहे हैं, परन्तु क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके बीच मतभेद भी हुए हैं। मुख्य रूप से क्षेत्रीय नेतृत्व, मुस्लिम ब्रदरहुड, सीरिया, कतर और मिस्र जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ है। दोनों देशों की क्षेत्रीय नीतियों में अंतर अरब स्प्रिंग के बाद बढ़ा। इसके बाद दोनों देशों में धीरे-धीरे व्यावहारिक आधार पर संबंधों को पुनर्संतुलित किया और व्यापार, रक्षा क्षेत्र, निवेश तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाया। वर्तमान में तुर्किये की उभरती उन्नत रक्षा तकनीक और सऊदी अरब की आर्थिक क्षमता एवं रक्षा आधुनिकीकरण की ज़रूरतें दोनों देशों के मध्य वर्तमान संबंधों के प्रमुख आधार बन गई हैं।

तीनों देशों की विदेश नीति

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब की विदेश नीतियों का स्वरूप उनके राष्ट्रीय हितों, क्षेत्रीय परिस्थितियों और भौगोलिक परिवेश जैसे विभिन्न आयामों से प्रभावित होता है। तीनों देशों की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में अंतर होने के बाद भी क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक प्रभाव, ऊर्जा हित आदि जैसे क्षेत्रों में उनके हित एक-दूसरे से जुड़े हैं। वर्तमान में बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यही साझा हित तीनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग का प्रमुख आधार बन रहे हैं।

पाकिस्तान की विदेश नीति में भौगोलिक परिवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को विशेष महत्व प्राप्त है। भारत के साथ लंबे समय से चले जा रहे सीमा विवाद तथा कश्मीर मुद्दे के कारण पाकिस्तान अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करने पर जोर देता है जो उसकी सुरक्षा एवं आर्थिक आवश्यकताओं में सहयोग कर सकें। चीन के साथ सी०पी०ई०सी०, तुर्किये के साथ रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग सऊदी अरब के साथ आर्थिक, धार्मिक एवं सुरक्षा संबंध उसकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

तुर्किये की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना तथा रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करना है। तुर्किये नाटो का सदस्य होने के बावजूद न केवल पश्चिमी देशों बल्कि रूस, खाड़ी देशों, मध्य एशिया और एशिया के अन्य देशों के साथ भी अपने सक्रिय संबंधों को विकसित करना चाहता है। तुर्किये के लिए रक्षा उद्योग और स्वदेशी सैन्य तकनीकी का विकास उसकी विदेश नीति का प्रमुख आधार है। वर्तमान में ड्रोन, मिसाइल और अन्य रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में उसकी बढ़ती क्षमता ने उसे क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाया है।

सऊदी अरब की विदेश नीति मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा हितों और खाड़ी क्षेत्र में अपने रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित रही है। अमेरिका के साथ लंबे समय से उसके रक्षा और सुरक्षा संबंध रहे हैं, परंतु वर्तमान में बदलते वैश्विक परिदृश्य में सऊदी अरब ने अन्य प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। इससे सऊदी अरब की विदेश नीति में व्यावहारिक एवं बहुदिशात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है।

तीनों देशों की विदेश नीतियों में अंतर होने के बावजूद सुरक्षा, आर्थिक हित, क्षेत्रीय प्रभाव जैसे कुछ साझा हित शामिल हैं। इन्हीं साझा हितों के कारण तीनों देशों के मध्य सहयोग के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।

उभरते सामरिक समीकरण के प्रमुख आयाम

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के मध्य उभरते गठजोड़ में न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक, धार्मिक, रक्षा एवं सैन्य सहयोग, भौगोलिक महत्व एवं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे विभिन्न आयाम शामिल हैं। तीनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा विदेशनीतियों में अंतर होने के बाद भी कुछ साझा हित इन्हें सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। इन संबंधों को भिन्न-भिन्न आयामों के माध्यम से समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं-

इस सामरिक गठजोड़ का सबसे महत्वपूर्ण आधार रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग है। पाकिस्तान और तुर्किये के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण, नौसैनिक सहयोग, उत्पादन एवं तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण है। तुर्किये की उभरती रक्षा उद्योग क्षमताओं ने पाकिस्तान के लिए सहयोग के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मध्य भी लंबे समय से रक्षा और सुरक्षा संबंध रहे हैं। यदि इन द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक त्रिपक्षीय ढांचे में समन्वित किया जाता है, तो यह पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण पर प्रभाव डाल सकता है।

आर्थिक हित भी इस त्रिपक्षीय गठजोड़ को एक-दूसरे के साथ लाने वाला महत्वपूर्ण कारक हैं। सऊदी अरब की वित्तीय क्षमता, तुर्किये की औद्योगिक एवं रक्षा क्षमता तथा पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे की पूरक हो सकती हैं। सऊदी अरब निवेश के माध्यम से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और विकास में सहयोग प्रदान कर सकता है। साथ ही तुर्किये के साथ सहयोग पाकिस्तान में रक्षा एवं विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार, निवेश और अवसंरचना एवं ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से त्रिपक्षीय गठजोड़ को रणनीतिक आधार प्रदान करता है। तीनों देश इस्लामिक विश्व में भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल एवं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तुर्किये की पश्चिम एशिया और मुस्लिम विश्व में राजनीतिक प्रभावशीलता है, जबकि सऊदी अरब धार्मिक महत्व के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व रखता है। इस कारण इस्लामी विश्व से जुड़े मुद्दों पर इन देशों के मध्य कूटनीतिक एवं राजनीतिक समन्वय की संभावना प्रबल हो जाती है।

बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी महत्वपूर्ण आधार है। भारत के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, वहीं तुर्किये पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जबकि सऊदी अरब पश्चिम एशिया में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रभावित करना चाहता है। अतः तीनों देशों के मध्य बढ़ता आपसी सहयोग क्षेत्रीय शक्तियों की प्रभावशीलता को संतुलित करने का माध्यम बन सकता है।

तीनों देशों की भौगोलिक स्थिति इनके सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ाती है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया और अरब सागर के मध्य स्थित है, तुर्किये यूरोप और एशिया के मध्य स्थित होने के साथ काला सागर और भूमध्य सागर से जुड़ा है, जिससे उसका महत्व यूरोप, पश्चिम-एशिया और यूरेशिया के संदर्भ में बढ़ जाता है, वहीं सऊदी अरब फारस की खाड़ी और लाल सागर के बीच स्थित होने के कारण समुद्री मार्गों एवं ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है।

नाटो की तुलना

वर्तमान में तीनों देशों के मध्य बढ़ता रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग विशेष रूप से रणनीतिक महत्व रखता है, परंतु उनकी तुलना अभी नाटो जैसे औपचारिक और संस्थागत सैन्य गठबंधन से करना उचित नहीं होगा, इसके प्रमुख कारण हैं, जैसे एकीकृत सैन्य कमान का अभाव, साझा सैन्य बलों का अभाव अर्थात् इनके पास स्थायी संयुक्त सैन्य बल, साझा परिचालन योजना या एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं का अभाव है, सुरक्षा संबंधी धारणाओं में भिन्नता, परमाणु सुरक्षा-छत्र का अभाव जैसे विभिन्न कारण शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब सामरिक समीकरण अभी साझा हितों और आपसी रक्षा सहयोग पर आधारित प्रतीत होता है। नाटो के पास स्थायी संस्थागत ढांचा, सैन्य कमान, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया एवं सामूहिक रक्षा जैसी स्पष्ट व्यवस्थाएँ शामिल हैं। इसलिए वर्तमान में इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन के बजाय उभरता हुआ सामरिक अभिसरण कहना अधिक उचित होगा।

सी०पी०ई०सी० पर प्रभाव

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के मध्य बढ़ता आपसी सहयोग सी०पी०ई०सी० की आर्थिक एवं सामाजिक उपयोगिता को प्रभावित कर सकता है। सी०पी०ई०सी० चीन की बी०आर०आई० की प्रमुख परियोजना है, जो चीन को पाकिस्तान के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह और अरब सागर से जोड़ती है। यदि सऊदी अरब के माध्यम से सी०पी०ई०सी० से जुड़ी ऊर्जा, खनन, निवेश और औद्योगिक क्षेत्र जैसी परियोजनाओं में अधिक निवेश किया जाता है तथा तुर्किये द्वारा व्यापार एवं परिवहन के क्षेत्र में संपर्कों को विस्तार दिया जाता है, तो सी०पी०ई०सी० का महत्व और अधिक बढ़ सकता है तथा कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क का रूप ले सकता है। भारत के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सी०पी०ई०सी० का एक भाग पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत द्वारा अपनी संप्रभुता का दावा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त ग्वादर बंदरगाह एवं अरब सागर में बढ़ती पाकिस्तानी गतिविधियाँ भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक हैं। सी०पी०ई०सी० को सीधे सैन्य परियोजना का हिस्सा मानना उचित नहीं होगा। अतः भारत को इसके संभावित विस्तार का रणनीतिक आकलन करते हुए चाबहार, भारत-मध्य पूर्व-आर्थिक गलियारे, मध्य एशिया से संपर्क एवं हिंद महासागर में अपनी समुद्री क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिससे भारत के व्यापारिक हित, भू-आर्थिक एवं सामरिक स्थिति मजबूत होगी।

अमेरिका, चीन और रूस की भूमिका

पश्चिम-एशिया और दक्षिण-एशिया की भू-राजनीति में अमेरिका, चीन, रूस की भूमिका उनके भिन्न-भिन्न सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों से प्रभावित होती है। अमेरिका की सऊदी अरब के साथ सुरक्षा व आर्थिक साझेदारी तथा भारत-अमेरिका के मध्य रक्षा तकनीकी एवं इंडो पेसिफिक सहयोग महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका, पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब को केवल भारत विरोधी दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, बल्कि अपने व्यापक पश्चिम-एशिया और इंडो-पेसिफिक हितों के संदर्भ में इसका आकलन कर सकता है।

चीन, पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी और सी०पी०ई०सी० के माध्यम से जुड़ा है तथा सऊदी अरब के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। यदि भविष्य में चीन की बी०आर०आई० तथा अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएँ इस त्रिपक्षीय समीकरण से जुड़ती हैं, तो पाकिस्तान की आर्थिक व सामरिक क्षमताओं का विस्तार हो सकता है। इसलिए यह भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि वर्तमान में तीनों देशों के चीन के साथ संबंधों की प्रकृति भिन्न-भिन्न है, इसलिए इसे वर्तमान में चीन समर्थित गठबंधन के रूप में देखना उचित नहीं होगा। रूस की भूमिका मुख्यतः ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर आधारित है। रूस के तुर्किये व सऊदी अरब के साथ आर्थिक एवं

रणनीतिक संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर, भारत के साथ उसके लंबे समय से रक्षा और रणनीतिक संबंधों में साझेदारी रही है। इसलिए रूस किसी एक पक्ष के साथ जुड़ने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर सकता है।

भारत के लिए संभावित चुनौतियाँ

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के मध्य बढ़ता सामरिक सहयोग भारत के लिए रक्षा, कूटनीतिक, ऊर्जा, समुद्री एवं आर्थिक स्तर पर विभिन्न संभावित रणनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। जिसमें सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में पाकिस्तान की सामरिक क्षमता में संभावित वृद्धि है। सऊदी अरब के आर्थिक सहयोग तथा तुर्किये के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग से पाकिस्तान सैन्य आधुनिकीकरण, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकता है। मुख्य रूप से ड्रोन, लड़ाकू विमान, नौ सैनिक एवं वायु रक्षा प्रणालियों जैसे विभिन्न सैन्य तकनीकों में सहयोग पाकिस्तानी सैन्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जिसका प्रभाव संभावित रूप से भारत के पारंपरिक सैन्य लाभ पर पड़ सकता है।

सऊदी अरब भारत के ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण साझेदार है। दूसरी ओर, सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक और सुरक्षा के रहे हैं। यदि भविष्य में पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के मध्य सहयोग अधिक व्यापक होता है, तो भारत के लिए पश्चिम एशिया में अपने विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब के भारत के साथ व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक हितों को देखते हुए उसके संबंधों को भारत विरोधी गठजोड़ के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

तीनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से उनकी रणनीतिक उपस्थिति पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर पश्चिमी हिंद महासागर तक विस्तारित हो सकती है, यह वह क्षेत्र है जहाँ भारत स्वयं को एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

पाकिस्तान और चीन के मध्य काफी लंबे समय से एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें सीपीईसी प्रमुख भूमिका निभाता है। इस त्रिपक्षीय गठजोड़ के मध्य बढ़ता सहयोग यदि भविष्य में चीन की क्षेत्रीय एवं आर्थिक पहलों से जुड़ा है, तो दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में भारत के लिए रणनीतिक वातावरण अधिक जटिल बन सकता है। हालांकि चीन के साथ तीनों देशों के संबंधों की प्रकृति और उनके राष्ट्रीय हित समान नहीं हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में संभावित सामरिक अभिसरण को एक संगठित भारत विरोधी या चीन समर्थित सैन्य संगठन के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

यदि इस गठजोड़ के मध्य आपसी सहयोग आने वाले समय में लगातार बढ़ता है, तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य एक नया रणनीतिक संपर्क विकसित होने की संभावना रहेगी। जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए बदलती परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा नीतियों को प्रभावी ढंग से समायोजित करना होगा।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया की स्थिरता से जुड़ी है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सऊदी अरब सहित इस क्षेत्र पर निर्भर है। पश्चिम एशिया में किसी बड़े राजनीतिक तनाव या सैन्य संघर्ष की स्थिति तेल की कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने तथा सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब का बढ़ता सहयोग साझा धार्मिक पहचान, सामरिक, आर्थिक और क्षेत्रीय हितों पर आधारित है। तीनों देशों की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं तथा विदेश नीतियों में अंतर होने के बाद भी रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक हित एवं मुस्लिम जगत में प्रभावशालीता स्थापित रखने जैसे मुद्दे उन्हें आपसी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में यह सहयोग अभी नाटो जैसे औपचारिक सैन्य गठबंधन का रूप नहीं ले पाया है, परन्तु रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में इसकी बढ़ती निकटता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव डाल सकती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सामूहिक आत्मरक्षा का आधार प्रदान करता है, परन्तु इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना आवश्यक है। अतः तीनों देशों के मध्य संबंधों को उभरते हुए क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वर्तमान में यह साझेदारी विकासशील अवस्था में है और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि तीनों देश अपने भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के मध्य कितने प्रभावी ढंग से संतुलन स्थापित कर पाते हैं। यदि यह साझेदारी भविष्य में अधिक संगठित और संस्थागत रूप लेती है, तो दक्षिण एशिया एवं पश्चिमी एशिया की रणनीतिक परिस्थितियों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। भारत के संदर्भ में ऐसी परिस्थितियों में किसी

एक गुट के साथ जुड़ने के स्थान पर बहुपक्षीय कूटनीति, ब्रिक्स, रणनीतिक स्वायत्तता तथा विभिन्न राष्ट्रों के साथ संतुलित संबंध स्थापित करना अधिक प्रभावशाली होगा।

संदर्भ सूची

- [1]. The Economist. (2026, August 13). What to make of a new Saudi-led defence pact: Turkish arms producers may be the first beneficiaries. The Economist.
<https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2026/08/13/what-to-make-of-a-new-saudi-led-defence-pact>
- [2]. Nawaz, N. (2026, August 25). Mecca defence pact and the question of an Islamic NATO. Centre for Strategic and Contemporary Research.
<https://cscr.pk/explore/themes/defense-security/mecca-defence-pact-and-the-question-of-an-islamic-nato/>
- [3]. Flora, S. S. (2026, August 23). The future of Islamic NATO. The Pioneer.
<https://dailypioneer.com/news/the-future-of-islamic-nato>
- [4]. Aspire IAS. (2026, August 10). Mecca Joint Defence Agreement: Pakistan, Saudi Arabia, Türkiye.
<https://aspireias.com/blogs/mecca-joint-defence-agreement>
- [5]. Astier, H., & Inwood, J. (2026, August 7). Saudi Arabia, Turkey and Pakistan sign defence pact. BBC News.
<https://www.bbc.com/news/articles/c30418m4mj4o>
- [6]. Shekhawat, S. (2026, August 13). A new axis in West Asia: Reading the new Saudi-Turkish-Pakistani defence pact. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/a-new-axis-in-west-asia-reading-the-new-saudi-turkish-pakistani-defence-pact>
- [7]. Akbar, M. J. (2026, August 28). An Islamic NATO: The Mecca mirage. Open.
<https://openthemagazine.com/world/an-islamic-nato-the-mecca-mirage>
- [8]. Drishti IAS. (2026, August 12). Implications of the Mecca Joint Defence Agreement for India. Drishti IAS.
<https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/mecca-joint-defence-agreement-and-its-implications-for-india>
- [9]. Joshi, M. (2026, January 24). "Islamic NATO"-Fiction or reality? And why India should prepare. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/hindi/research/islamic-nato-fiction-or-reality-and-why-india-should-prepare>
- [10]. Vajiram Mains Team. (2026, August 11). Mecca agreement: Saudi Arabia, Turkey and Pakistan's new defence pact and India. Vajiram & Ravi.
<https://vajiramandravi.com/current-affairs/mecca-agreement-saudi-arabia-turkey-and-pakistans-new-defence-pact/>
- [11]. Aslam, W. (2026). Pakistan's foreign policy: Security, state, and society. Oxford University Press.
- [12]. Amin, S. M. (2022). Pakistan's foreign policy: A reappraisal (3rd ed.). Oxford University Press.
- [13]. Borck, T. (2024). Seeking stability amidst disorder: The foreign policies of Saudi Arabia, the UAE and Qatar, 2010–20. Oxford University Press.
- [14]. Singh, M. (2025). India and the Gulf: A security perspective. Routledge.

Cite this Article:

निधि कटियार., & डी० सी० कटियार (2026). पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब सामरिक गठजोड़ का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. *International Journal of Humanities, Commerce and Education*, 2(9), 14–19.

Journal URL: <https://ijhce.com/>

DOI: <https://doi.org/10.59828/ijhce.v2i9.137>

Disclaimer/Publisher's Note: The author(s) are solely responsible for the content and claims of this article. The publisher and editors assume no legal liability for any errors, copyright violations, or damages arising from its use.